क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 50, गुरुवार, 14 मार्च, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

मायावती से मिलने पहुंचे अखिलेश, आज होने वाली बैठक में हो सकता है प्रत्याशियों का ऐलान

लखनऊ। 17वीं लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गई हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए सपा-बसपा के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बुधवार को देर शाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 मॉल एवेन्यू आवास पर बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों दलों के सीटों और प्रत्याशियों को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे इस बैठक में मायावती लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। इससे पहले मंगलवार को मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए सभी राज्यों के बसपा प्रमुखों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सपा-बसपा ने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भी आपसी समझ और सूझबूझ से गठबंधन किया है। बसपा और सपा का गठबंधन पूरी नेकनीयती से काम कर रहा है और तीनों राज्यों में इसे बेहतर गठबंधन के तौर पर माना जा रहा है। मायावती ने पार्टीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पार्टी से जुड़ सभी लोगों को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि वे थोड़े समय के लाभ के लिए ऐसा कोई कदम न उठाएं जो पार्टी के हित में न हो। बता दें कि, बसपा सुप्रीमो ने पिछले दिनों संगठन का पुनर्गठन करने के बाद मंडल व जिले स्तर पर बैठकों का निर्देश दिया था। जिला स्तर पर सपा-बसपा की साझा बैठकें जारी हैं। ये बैठकें 18 मार्च तक प्रस्तावित हैं।

ममता बनर्जी का दावा- सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी टीएमसी

नेशनल डेस्क। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेने का दावा किया है। बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में राज्य में 'क्लीन स्विप' करेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के तहत 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक सात चरणों में मतदान होंगे। तृणमूल ने मंगलवार को राज्य की सभी 42 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें 41 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिये गये हैं। इनमें चार अभिनेत्री शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में तृणमूल ने 35 फीसदी महिलाओं को टिकट दिये थे। टीएमसी की उम्मीदवारों की सूची में टॉलीवुड की अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां शामिल हैं। वहीं घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 40.5 फीसदी महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। यह हमारे लिए एक गर्व का क्षण है। आसनसोल से हमारी उम्मीदवार मुन मुन सेन होंगी और बीरभूम से सताब्दी रॉय को कैंडिडेट घोषित किया गया है।

ट्वीट पर पीएम मोदी ने राहुल समेत कई प्रमुख हस्तियों को किया टैग सरकार

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्म जगत समेत अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आगे आने की बुधवार को अपील की और कहा कि सब लोग मिलकर यह दिखा दें कि इस बार अभूतपूर्व मतदान होगा जो देश के चुनावी इतिहास के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। प्रधानमंत्री ने बुधवार को ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन समेत कई नेताओं को टैग कर अपील की कि वे मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मोदी ने ट्वीट किया, मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, पवार, मायावती, अखिलेश यादव, (बिहार में नेता प्रतिपक्ष) तेजस्वी यादव और एम के स्टालिन से अपील करता हूं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अधिक मतदान हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा, मैं (तेलंगाना के मुख्यमंत्री) के. चंद्रशेखर राव, (ओडिशा के मुख्यमंत्री) नवीन पटनायक, (कर्नाटक के मुख्यमंत्री) एच डी कुमारस्वामी, (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) एन चंद्रबाबू नायडू और (आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता) वाईएस जगन मोहन रेड्डी से अपील करता हूं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों में अधिकतम भारतीयों को लाने के लिए काम करें। उन्होंने नीतीश कुमार, राम विलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल, चिराग पासवान, आदित्य ठाकरे सहित कैलाश सत्यार्थी, किरण बेदी, अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर, सदुरू, योगगुरू रामदेव के अलावा मोहन लाल, नागार्जुन से अपील की कि वे लोगों को मतदान करने के महत्व को बताएं। उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल, कोनराड सांगमा, हेमंत विस्व शर्मा, नेफियू रियो से अपील कि वे लोगों से बतायें कि अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये महत्वपूर्ण है । मोदी ने एशियन न्यूज इंटरनेशल की संपादक स्मिता प्रकाश और समाचार एजेंसी पीटीआई समेत मीडिया जगत से भी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने श्रीश्री रविशंकर समेत आध्यात्मिक जगत के नेताओं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, पहलवान सुशील कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू और सायना नेहवाल समेत खेल जगत की हस्तियों से भी मतदाताओं को जागरूक बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने एम एस धोनी, विराट कोहली, अनिल कुंबले, वीरेन्द्र सहवाग के अलावा फोगाट बहनों, बजरंग पुनिया, नीरज आदि से भी जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने क्रिकेटरों से कहा कि आप क्रिकेट के मैदान में अभूतपूर्व रिकार्ड बनाते हैं, अब आप 130 करोड़ भारतीयों को मतदान का नया रिकार्ड बनाने में योगदान देने के लिये प्रेरित करें। कुश्ती से जुड़े खिलाड़ियों से मोदी ने अपील कि हमने आपको दंगल के मैदान में देखा है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लोगों को चुनावी दंगल में हिस्सेदारी के लिये प्रेरित करें। उन्होंने लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान, रणवीर कपूर, वरुण धवन, विक्की कौशल, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा, आयुष्मान खुराना, रनवीर सिंह, अक्षय कुमार, भूमि पेंडनेकर, करण जौहर, मनोज वाजपेयी समेत कला जगत की हस्तियों से भी कहा कि वे मतदाताओं से मतदान केंद्रों में आने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करने की अपील करें। फिल्मी हस्तियों से मतदाताओं को जागरूक बनाने की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि समय आ गया है कि आप अपने अंदाज में लोगों को मतदान के लिये प्रेरित करें। इस प्रकार से हम अपने लोकतंत्र और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा, थोड़ा दम लगाइयें और वोटिंग को एक सुपरहिट कथा बनाइयें। मतदान केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है। हमें लोगों में जागरूकता बढ़ानी है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी संप्रग सरकार : राहुल

चेन्नई।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करता है, तो वह महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण और लोकसभा में 33 फीसदी सीटें प्रदान करने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगा। यहां स्टेला मैरिस कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं से बात करते हुए गांधी ने यह भी कहा कि संप्रग सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया को आसान बनाएगी और कर की एक दर रखेगी। टी-शर्ट और जीन्स पहने राहुल को आर्थिक विकास, जम्मू एवं कश्मीर में शांति लाने के बारे में कांग्रेसनीत संप्रग की योजना, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपों, मोदी सरकार के बारे में उनके विचार और संसद में नरेंद्र मोदी को गले लगाने के कारणों के बारे में छात्राओं के सवालों का सामना करना पड़ा। देश में महिलाओं की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में हालात बेहतर हैं। यह एक सांस्कृतिक पहलू है। लेकिन, उन्होंने तुरंत कहा, तमिलनाडु में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर संप्रग सरकार सत्ता में आती है तो महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकारों में 33 फीसदी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। उन्होंने कहा, प्यार हर धर्म की बुनियाद है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो। मैं संसद में प्रधानमंत्री का भाषण देख रहा था, जहां वह मेरे पिता, दादी, परदादा और कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। राहुल ने कहा, अपने भीतर मैं उनके प्रति स्नेह महसूस कर रहा था। वह इतना गुस्से में थे कि वह दुनिया की सुंदरता नहीं देख पा रहे थे। राहुल ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि मोदी को वह प्यार नहीं मिला जो वह चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं स्नेह दिखाना चाहता था और इसलिए मैंने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 में संप्रग की हार ने उन्हें कई सबक सिखाए। उन्होंने कहा, मैं मोदी से सीखता हूं। मैं उनसे नफरत नहीं करता। क्या आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो आपको सिखाता है? गांधी ने छात्राओं से यह पूछा और जवाब में छात्राओं ने न कहा। राहुल ने कहा, सबसे बड़े शिक्षक वो लोग हैं जो हमला करते हैं। जितना अधिक आप पर हमला किया जाता है, उतना ही प्यार और स्नेह वापस आप देते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में शांति वापस लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहला कदम वहां के लोगों से संपर्क करना है। संपर्क के इस पुल को संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, आतंकी हमलों में भारी कमी आई थी ।

प्रधानमंत्री भी कर रहे महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपीलः अखिलेश

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी भी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी भी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन को टैग कर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इन सभी से लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करने के लिए कहा था।

आसमान में भी चुनावी लड़ाई, बीजेपी ने बुक कर लिए देश के 60 फीसद हेलिकॉप्टर

नई दिल्ली । लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियों ने जोरदार कैंपेनिंग की तैयारी कर ली है। इस दौरान जहां रैली व रोड शो जरिये नेता अपना दमखम दिखाएंगे, वहीं एक चुनावी लड़ाई आसमान में भी लड़ी जाने वाली है। ये लड़ाई ज्यादा से ज्यादा हेलिकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक कराने के लिए हो रही है। इसके चलते हेलिकॉप्टर और चार्टेड प्लेन कंपनियों की चांदी हो गई है। हालत यह है कि इस बार पूरे चुनाव सीजन के लिए जहाज बुक हो चुके हैं ताकि दूसरी पार्टी को हेलिकॉप्टर ना मिल सकें। बता दें कि भारत में लगभग 260 हेलिकॉप्टरऔर 200 चार्टेड प्लेन्स हैं। इस बीच, इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने महीनों पहले ही देश के लगभग 60 फीसदी हवाई जहाजों की बुकिंग करा ली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी आक्रामक तरीके से हेलिकॉप्टर की बुकिंग इस बार हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। उधर, कांग्रेस की शिकायत है कि उसके पास बुकिंग के लिए जहाज ही नहीं हैं। इस बार एक और ट्रेंड यह दिख रहा है कि कई स्थानीय दल , खासतौर पर महागंठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के साथ हेलिकॉप्टर की शेयरिंग भी रह रही हैं। यह भी जानकारी मिली है कि आम दिनों के मुकाबले हेलिकॉप्टर के प्रति घंटे के किराए दोगुने -तिगुने तक हो गए हैं। मतलब साफ है कि एक नेता के एक दिन के प्रचार के लिए पार्टियों को 10-15 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है।

भाजपा का राहुल और प्रियंका पर बड़ा हमला, कहा-रक्षा दलालों से हैं संबंध

नयी दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया में आई रिपोर्टों का हवाला देते हुये बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पर रक्षा सौदे के दलालों के साथ साँठ-गाँठ का आरोप लगाया। ईरानी ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुये हैं उनमें यह तथ्य सामने आया है कि राहुल गाँधी ने हरियाणा के एच.एल. पहवा से जमीन खरीदी थी। राहुल गाँधी की बहन प्रियंका गाँधी वाड्रा और उनके जीजा राबर्ट वाड्रा के संबंध में भी कागजात बरामद हुये हैं। पहवा रक्षा सौदों के दलाल संजय भंडारी के एक नजदीकी सी.सी. थंपी का कर्मचारी है। भाजपा नेता ने कहा कि अब तक यह माना जा रहा था कि सिर्फ भंडारी और वाड्रा के बीच वित्तीय संबंध हैं, लेकिन अब यह स्थापित हो गया है कि भंडारी के संबंध गाँधी से भी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी को जवाब देना चाहिये कि उनके रक्षा सौदों के दलाल से क्या संबंध हैं। क्या इसीलिए वह देश के रक्षा सौदों में इतनी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से यह साफ है कि रक्षा सौदों में राहुल की रुचि सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं है; उनका वित्तीय हित भी इससे जुड़ा हुआ है।

चुनाव में होगा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल के दौरान देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए हैं और उनके सपनों को तोड़ा है इसलिए आम चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी साढे चार दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची है जबकि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पांच साल में देश के दस करोड़ युवाओं के लिए नौकरियों के नये अवसर उपलब्ध कराने की बात की थी लेकिन नोटबंदी करके उन्होंने डेढ करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली। उसके बाद आधा अधूरा जीएसटी लागू किया जिससे करोड़ों लोगों का कारोबार बंद हो गया। नौकरियों की हालत अब भी सुधर नहीं रही है और पिछले वर्ष दस लाख लोगों की नौकरियां चली गई। प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के समक्ष बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस अवधि में देश के किसानों की आय 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है।

मतदाताओं को जागरूक करने की मोदी की अपील झूठी.केजरीवाल

नई दिल्ली ।

आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों, अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों और संगठनों से मतदाताओं में जागरुकता लाने और अधिक से अधिक वोटरों को आम चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर बुधवार को की गई इस अपील में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं किया है । केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा ' प्रधानमंत्री जी, आपकी ये अपील झूठी है। आपके लोग लाखों लोगों के वोट कटवा कर उन्हें वोट करने से रोक रहे हैं। हमने उन लोगों के वोट बनवाए तो आपका अमित शाह हमारे काल सेंटर बंद करने की धमकी दे रहा है। अपने अमित शाह और अपनी दिल्ली पुलिस को रोकिए और या फिर ये झूठी अपील बंद कीजिए।' उन्होंने लिखा 'आज सुबह हमारे दो काल सेंटर पर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की रेड कराई। अब सारे काल सेंटर के मालिकों को थाने बुलाकर धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का काम बंद कर दो। अमित शाह, ऐसे चुनाव लड़ोगे? काल सेंटर वालों को क्यों तंग कर रहे हो? हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करो।' दिल्ली की सात संसदीय सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लडने की मंशा रखे हुए हैं । उन्होंने कहा ' देश के लोग अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को हराना चाहते हैं। अगर हरियाणा में जेजेपी. आप और कांग्रेस साथ लड़ते हैं तो राज्य की दसों सीटों पर भाजपा हारेगी । राहुल गांधी जी इस पर विचार करें।'

उद्धव ठाकरे का पवार पर पलटवार, कहा- मैं दूसरों के बच्चों की मांगों को भी करता हूं पूरा

नेशनल डेस्क।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय के भाजपा में शामिल होने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह दूसरे के बच्चों की मांगों को भी पूरा करने में विश्वास रखते हैं और उनका इस्तेमाल बर्तन साफ करवाने में नहीं करते। कांग्रेस के लिये बड़े झटके के तौर पर विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया था क्योंकि उन्हें अपना पहला लोकसभा चुनाव लडने के लिए अपने गृह क्षेत्र अहमद नगर से टिकट नहीं मिल सका था। सुजय ने ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी उम्मीदवारी के लिये शिवसेना के समर्थन की मांग की। अहमदनगर सीट कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी राकांपा के खाते में चली गई है और वह सुजय के लिये अहमदनगर सीट खाली करने को तैयार नहीं थी। ठाकरे ने कहा कि अपने बेटे की तरह, मैं दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करता हूं। यह शिवसेना की शैली नहीं है कि दूसरे के बच्चों का इस्तेमाल बर्तन साफ कराने के लिये करे। शिवसेना आम आदमी के लिये है। पवार ने कल सुजय के लिये अहमदनगर सीट न छोडने के फैसले को न्यायोचित ठहराया था। पवार ने राधाकृष्ण विखे पाटिल पर निशाना साधते हुए कल कहा था कि सजय विखे पाटिल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और चुनाव लडने के लिए एक खास सीट पर जोर दे रहे हैं। उनकी अपरिपक्व इच्छा को पूरा करना दूसरे दलों की जिम्मेदारी नहीं है। अपने बेटे की इच्छाओं को आपको खुद पूरा करना चाहिए, मैं अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे किसी दूसरे की इच्छा क्यों पूरी करनी चाहिए? ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने अपनी सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है जिसे अगले दो दिनों में जारी कर दिया जाएगा।

संपादकीय

सांसत में पाक

अमेरिका ने दो टूक शब्दों में पाक को आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की बाबत कहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से चरमपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर बातचीत की है। बोल्टन ने ट्वीट करके कहा है कि पाक के विदेश मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि पाक आतंकी संगठनों से सख्ती से निपटेगा। साथ ही यह भी कि भारत के साथ तनाव कम करने की दिशा में कोशिश जारी रखेगा। यह संकेत अमेरिका की यात्रा पर गये भारतीय विदेश सचिव वी. के. गोखले के अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के बाद सामने आए हैं। पुलवामा हमले और बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक से उपजे हालात से अवगत कराने अमेरिका गये विदेश सचिव ने जहां इस दौरान दिये गये सहयोग के प्रति अमेरिका का आभार जताया वहीं चरमपंथी संगठनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की भी मांग की। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना भी शामिल है। हालांकि, पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपने यहां कुछ चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रतिबंधित संगठनों द्वारा चलायी जा रही शिक्षण संस्थाओं को सीज किया, मगर ऐसे उपक्रम पहले भी अंतर्राष्ट्रीय जनमानस को भरमाने के लिए किये जाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिये सेना को दिये अधिकारों का भरपूर उपयोग करते हुए पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल मुदस्सिर अहमद खान समेत तीन चरमपंथियों को सुरक्षा बलों ने त्राल इलाके में मार गिराया। हालांकि, सेना ने पहले भी दावा किया था कि पुलवामा हमले के सौ घंटे के भीतर हमले के मास्टर माइंड को मार गिराया गया है। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी समेत तीन आतंकी मारे गये थे। सेना ने खुली चेतावनी भी दी थी कि जो बंदूक उठायेगा, वो मारा जायेगा। सेना दावा कर रही है कि पिछले तीन सप्ताह में अट्ठारह आतंकी मारे गये हैं। सेना वायुसेना द्वारा पाक स्थित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई से बने दबाव का लाभ उठाकर कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी संगठनों का सफाया करना चाहती है। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में बना है और दुनिया मान रही है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है, जिसका लाभ सेना को अपने लक्ष्य पाने में भी मिल रहा है। बहरहाल, सीमा पर पाक सेना की गोलाबारी और आतंकियों की सक्रियता से जाहिर है कि भारत को आतंक के खिलाफ लंबे समय तक जूझना होगा। ऐसे में दीर्घकालिक रणनीति बनाकर आतंक से मुठभेड़ की जरूरत है।

पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में बना है और दुनिया मान रही है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है, जिसका लाभ सेना को अपने लक्ष्य पाने में भी मिल रहा है।

पहल पर अमल करें

महिला आरक्षण/ प्रमोद जोशी

सन 1952 में पहली लोक सभा में केवल 4.4 फीसद महिला सदस्य थीं। सन 1977 में केवल 3.5 फीसद महिला सदस्य ही थीं। भारत के मुकाबले अफगानिस्तान की संसद में 27.7, पाकिस्तान में 20.6, बांग्लादेश में 19, नेपाल में 30 और सऊदी अरब की संसद में 19.9 फीसद महिलाएं हैं। वैश्विक औसत 21 से 22 फीसद का है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जन-प्रतिनिधित्व में स्त्रियों की भूमिका के लिहाज से भारत का दुनिया के देशों में 148वां स्थान है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि हम एक तिहाई सीटें महिला प्रत्याशियों को देंगे। प्रगतिशील दृष्टि से यह घोषणा क्रांतिकारी है और उससे देश के दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनेगा कि वे भी अपने प्रत्याशियों के चयन में महिला प्रत्याशियों को वरीयता दें। सत्रहवीं लोक सभा चुनाव में देश के 90 करोड़ मतदाताओं को भाग लेने का मौका मिलेगा, इनमें से करीब आधी महिला मतदाता हैं। पर व्यावहारिक राजनीति इस आधार पर नहीं चलती। आने दीजिए पार्टियों की सूचियां, जिनमें पहलवानों की भरमार होगी। राजनीति की सफलता का सूत्र है ''विनेबिलिटी' यानी जीतने का भरोसा। यह राजनीति पैसे और डंडे के जोर पर चलती है। पिछले लोक सभा चुनाव के परिणामों के विश्लेषण से एक बात सामने आई कि युवा और खासतौर से महिला मतदाताओं ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भूमिका इस बार के चुनाव में और बढ़ेगी, पर राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी आज भी कम है। कमोबेश दुनियाभर की राजनीति पुरुषवादी है, पर हमारी राजनीति में स्त्रियों की भूमिका नियंतण्र औसत से भी कम है। सामान्यत- संसद और विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 10 फीसद से ऊपर नहीं जाती। सोलहवीं लोक सभा के 542 सदस्यों में से स्त्री सदस्यों की संख्या 64 यानी कि 11.8 फीसद तक पहुंची। शुरुआती वर्षो में स्थिति और भी खराब थी। सन 1952 में पहली लोक सभा में केवल 4.4 फीसद महिला सदस्य थीं। सन 1977 में केवल 3.5 फीसद महिला सदस्य ही थीं। भारत के मुकाबले अफगानिस्तान की संसद में 27.7, पाकिस्तान में 20.6, बांग्लादेश में 19, नेपाल में 30 और सऊदी अरब की संसद में 19.9 फीसद महिलाएं हैं। वैश्विक औसत 21 से 22 फीसद का है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जन-प्रतिनिधित्व में स्त्रियों की भूमिका के लिहाज से भारत का दुनिया के देशों में 148वां स्थान है। इस विषय पर आगे बात करने से पहले नवीन पटनायक की पहल पर नजर डालें। पटनायक उस महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में थे, जो संसद से आज तक पास नहीं हो पाया है। सन 1996 से 2008 तक संसद में चार बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किए गए हैं, पर राजनीतिक दलों ने उन्हें पास होने नहीं दिया। नवीन पटनायक को कम-से-कम इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इसे दूसरे रास्ते से लागू करने की कोशिश की है। ओडिशा विधानसभा महिला आरक्षण के पक्ष में सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र से मांग कर चुकी है कि स्त्रियों को जन-प्रतिनिधित्व में 33 फीसद आरक्षण दिया जाए। ओडिशा की कुल 21 लोक सभा सीटों में से पिछली बार 20 पर बीजू जनता दल को विजय मिली थी। इनमें केवल तीन महिला सदस्य थीं। एक तिहाई के वायदे को पूरा करने के लिए इस बार बीजद को 21 में से सात पर महिला प्रत्याशियों को टिकट देना होगा। सात महिला प्रत्याशी खड़े करने के लिए उन्हें कम-से कम तीन ऐसे प्रत्याशियों का पत्ता काटना होगा, जो पिछली बार जीते थे। बैजयंत पांडा पहले से हट चुके हैं, इसलिए यह संख्या तीन है वरना चार होती। यह काम अपेक्षाकृत सरल है। ज्यादा मुश्किल काम तब होता, जब वे विधानसभा चुनाव में भी एक तिहाई महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करते। पार्टियों के प्रत्याशियों का चयन करते समय आंतरिक कोटा तय करने की बात आकर्षक जरूर है, पर व्यावहारिक रूप से यह भी काफी मुश्किल काम है। दिसम्बर के महीने में जब संसद में ट्रिपल तलाक विधेयक पर विचार चल रहा था, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि राजनीतिक दलों को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिया जाना चाहिए। सच यह है कि ममता ने अपनी पार्टी में 33 फीसद सीटें महिलाओं को देने का फैसला नहीं किया है। सच यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस आरक्षण के पक्ष में हैं। दोनों चाहें तो यह विधेयक पास हो सकता है, पर पास नहीं होता। सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? 24 अप्रैल 1993 को भारत में संविधान के 73वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दरजा हासिल कराया गया। यह फैसला ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम था, पर उतना ही महत्वपूर्ण महिलाओं की जीवन में भागीदारी के विचार से था। इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी। यह कदम क्रांतिकारी साबित हुआ। पंचायत राज में अब दूसरी पीढ़ी की युवा लड़कियां सामने आ रहीं हैं। महिलाओं की भूमिका में युगांतरकारी बदलाव आया है। अब यह आरक्षण 50 प्रतिशत हो रहा है। जब स्थानीय निकायों में आरक्षण से बदलाव आया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? पार्टियों के भीतर क्रमिक रूप से स्त्रियों के महत्व को स्थापित करने और सीटों के आवंटन में उन्हें वरीयता देने से ही अब यह काम होगा। दुनिया के कई देशों में इसे सफलता भी मिली है। मसलन स्वीडन की संसद में सीटों का कोटा नहीं है, बल्कि पार्टियों के भीतर कोटा है। वहां संसद में 47 फीसद स्त्रियों की उपस्थिति है। अर्जेंटीना में सीटों का भी कोटा है और पार्टियों के भीतर भी कोटा है। वहां 40 फीसद स्थान स्त्रियों के पास है। नॉर्वे की संसद में 36 फीसद महिला सदस्य हैं। इस काम के लिए स्त्रियों की पहल और सामाजिक समर्थन की जरूरत भी है। हमारे यहां पहिया उल्टा घूम रहा है। पहले राजनीति में साफ छवि के लोग जाते थे। अब अपराधियों की भूमिका बढ़ रही है। इस वजह से एक बड़ा तबका राजनीति को अच्छी निगाहों से नहीं देखता, खासतौर से स्त्रियां। जब महिलाएं बैंकों, कॉरपोरेट हाउसों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, सेना, हवाई जहाजों, रेल-इंजनों और मीडिया हाउसों का संचालन कर रहीं हैं, तो वे संसद और विधानसभाओं की कार्य-पद्धति में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकतीं हैं। सत्ता के केंद्र की चाभी स्त्रियों के हाथ में लगेगी, तभी बड़े बदलावों की उम्मीद करनी चाहिए। जन-प्रतिनिधि के रूप में ही स्त्रियां उन संरचनात्मक अवरोधों को गिराएंगी, जो समस्या के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। पर यह काम एकतरफा तरीके से नहीं हो सकता। नवीन पटनायक की इस पहल से कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इसे महिला वोटरों को खुश करने की कोशिश कह सकते हैं। फिलहाल इतना ही काफी है।

आज का राशीफल

मेष आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने बहुमूल्य सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी का सहयोग रहेगा।

वृषभ व्यावसायिक योजना सफल होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। त्वचा उदर या वायु विकार की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। किया गया प्रयास सफल होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। परिश्रम अधिक करना होगा।

कर्क पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

सिंह पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कन्या व्यावसायिक व पारिवारिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। अनचाही यात्रा या विवाद में फंस सकते हैं।

तुला बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। विरोधी शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता या संबंधित अधिकारी से तनाव मिलेगा।

वृश्चिक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। मैत्री संबंध में प्रगाढ़ता आयेगी।

धनु शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजना हो सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

मकर रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। रोग और विरोधी बढ़ेंगे। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें।

कुम्भ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा।

मीन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

हर क्षण का करें उपयोग

– डॉ. दीपक आचार्य

समय ही पूरी दुनिया की वह धुरी है जिसके इर्द-गिर्द सृष्टि घूमती है और पिण्ड से लेकर ब्रह्माण्ड तक सभी कारक प्रभावित होते हैं। काल का अनवरत गतिमान चक्र न किसी का सगा होता है न दुश्मन। वह अपनी धुरी पर अनथक गतिमान है और रहेगा। न कोई इसे रोक सका है, न मनमाफिक चलाने का दुस्साहस कर सका है। इस सत्य से वाकिफ होने के बावजूद लोग समय को मान नहीं देते, समय के साथ नहीं चल पाते, समय की उपेक्षा करते हैं। ध्रुव सत्य यही है कि आज का समय अपना है, आने वाली घड़ी या कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि समय उनके अनुरूप चले, और ऐसा हो पाना कभी संभव है ही नहीं। मनुष्य के रूप में संसार में अवतरण के उपरान्त एकमात्र समय ही वह सर्वोपरि कारक है जिसके बारे में हर जीवात्मा को सचेष्ट होकर इसका पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम कर्म के माध्यम से आने वाले समय के प्रारब्ध और भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सारी योनियां केवल भोग पूर्णता के लिए हैं, कर्म के माध्यम से ऊर्ध्वगति पाने के लिए नहीं। यह हम पर निर्भर है कि हम ऊर्ध्वरेता बनकर उच्चतर अवस्था और उच्चतम लोकों की यात्रा करें या फिर अधोगति की ओर गमन करें। अधिकांश लोगों की जिन्दगी की असफलता का यही कारण है कि वे लोग समय के मोल को नहीं पहचानते हैं और इंसानी जीवन को केवल टाईमपास का पर्याय मानकर बैठे रहते हैं। जो समय को सम्मान नहीं देता, उसे समय भी तिरस्कृत कर देता है और जिसे समय नकार देता है, उपेक्षित कर देता है, उसका विधाता भी भला नहीं कर सकते। समय के मामले में लोगों की भिन्न-भिन्न आदतें हैं। कोई इसे सायास गुजारने के लिए मनोरंजन के मार्गों का सहारा लेते हैं, कोई यह मानते हैं कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक जैसे-तैसे इस शरीर को घसीटना ही है। खूब सारे मानते हैं कि शरीर मिला है तो जमकर भोग करो, पता नहीं बाद में यह शरीर मिले न मिले। कुछ फीसदी लोग ही ऐसे होते हैं जो कि समय का पूरा-पूरा सदुपयोग करते हैं और कालजयी कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो समय के साथ नहीं चलता, समय के महत्व को अंगीकार नहीं करता, उसे समय ऐसा भुला देता है कि उसके रहते हुए भी, और जाने के बाद भी उसका नामलेवा तक कोई नहीं रहता। पता ही नहीं चलता कि ये लोग कब संसार में आए और कब चले गए। बहुत थोड़े ही लोग ऐसे बचे होंगे जो कि समय के अनुशासन का पूरी तरह पालन करते हैं और अपने हर काम समय पर करते हैं, समय के साथ चलते हैं और वर्तमान समय के एक-एक सैकण्ड को मान देते हैं, उसका पूरा उपयोग करते हैं। इनके अलावा में वे सारे लोग आ जाते हैं जो समय के मामले में अनुशासनहीन, उन्मुक्त और हद दर्जे के स्वेच्छाचारी हैं। ये लोग आलसी, प्रमादी और शैथिल्यग्रस्त होते हैं। इनमें दो किस्मों के लोग हैं। एक प्रजाति उनकी है जिसे समय की पहचान नहीं है, समय के महत्व से अनभिज्ञ हैं और जीवन भर यही तनाव बना रहता है कि टाईमपास कैसे करें। ऐसे लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता, जमाने भर की गंदगी के छिद्रान्वेषण और निन्दा के अलावा इनके जीवन में और कोई दूसरा काम होता ही नहीं। ये लोग उन सभी विषयों और क्षेत्रों की तरफ ताक-झाँक करते हैं जिनसे इनका कोई लेना-देना नहीं होता। असल में यही वे लोग हैं जो समाज और परिवेश में गंदगी का परिवहन करते हुए प्रदूषण फैलाते रहते हैं। ये लोग जिस तरह की हरकतें करते हैं उसे देखकर यही लगता है कि ये अपने पिछले जनम में सूअर, गिद्ध या श्वानों की किसी प्रजातियों में कई सदियों तक रहे होंगे, तभी इनका स्वभाव जम गया है, तनिक भी नहीं बदला। इंसानी खोल पा जाने के बावजूद पुराने जन्मों की आदतें बरकरार हैं। इन्हीं में काफी सारे लोग उन सभी कामों में रमे रहते हैं जिनका न इनकी जिन्दगी के लिए कोई उपयोग होता है, न समाज या देश के लिए। ऐसे लोग पृथ्वी पर वह अनचाहा बोझ हुआ करते हैं जिसे न इनके घरवाले पसन्द करते हैं, न सहकर्मी, मित्र और क्षेत्रवासी। इनका जीना बस जीना ही है, और वह भी जैसे-तैसे जी लेना। ऐसे लोग हर कहीं भारी तादाद में देखने को मिल जाते हैं। आजकल इस प्रजाति के कचराढोलू और बतरसिया लोगों की जनसंख्या हर कहीं बढ़ी हुई दिख रही है। हर तरह के बाड़ों और गलियारों, तमाम तरह के आम और खास पथों, चौराहों, सर्कलों और तिराहों से लेकर नुक्कड़ों और फुटपाथों तक इस किस्म के अजीबोगरीब जन्तु आसानी से देखे जा सकते हैं। इन्हीं की तरह के दूसरे लोग वे हैं जो समय के महत्व को अच्छी तरह जानते जरूर हैं लेकिन समय के अनुशासन का पालन नहीं कर पाते। ये लोग आलसी, दरिद्री और ढीले होते हैं इस कारण से समय की पाबंदी कभी नहीं रख पाते। इनका स्वभाव ही जिन्दगी भर के लिए ऐसा लापरवाह बन जाता है कि समय के प्रति कठोर नहीं रह पाते। समय उन सभी के साथ अत्यन्त भयानक और कठोर होता है जो समय के महत्व को तो स्वीकार करते हैं किन्तु उसका उपयोग करने में पीछे रह जाते हैं। कोई काम-काज न हो, ठाले बैठे हों, तब भी ये समय पर नहीं पहुँच पाते, चाहे काम-धंधों का स्थान हो या अपना दफ्तर। ये लोग बेवक्त धरती पर पैदा हो गए लगते हैं तभी कोई काम समय पर नहीं कर पाते। खुद तो समय के पाबंद नहीं होते, बल्कि औरों को भी अपनी तरह ढीठ और बेशर्म बना डालते हैं। यही कारण है कि इस किस्म के लोगों के बीच घनिष्ठता और दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। ये लोग इतने आलसी और कामचोर रहते हैं कि कोई काम समय पर नहीं करते। इनके जीवन की सबसे बुरी आदत होती है कोई काम समय पर नहीं करना, समय की पाबन्दी के प्रति हमेशा बेपरवाह रहना और समय का अनादर करना। इन सभी लोगों की यही आदत होती है कि जैसे-तैसे दिन गुजार लेना ताकि ज्यादा काम भी नहीं करना पड़े और हमारी मौजूदगी भी सुनिश्चित हो जाए। और जो मिलना है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आए। पता नहीं लोगों में बिना मेहनत के खाने की ये कैसी आदत पड़ गई है। ये लोग चाहते ही नहीं कुछ भी परिश्रम करना। मुफ्त में सब कुछ मिल जाए और जिन्दगी भर मजे करें। काम-धाम कुछ न करना पड़े, और आवक बढ़ती ही चली जाए। इसी उद्देश्य से ये लोग हर जगह कामचोरी के हथियार का इस्तेमाल कर माल जमा करते रहते हैं। बहुत सारे नुगरों का यही खेल है जो अर्से से चल रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या आज यही है। न समय का मान रहा है, न समय प्रबन्धन का खयाल। चाहे कितना कुछ कह डालो, खूब सारे नालायकों की भरमार है जो न समय पर आते हैं न कोई काम करते हैं और जाने की जल्दी हमेशा बनी रहती है। कोई काम न हो तब भी घर में पड़े रहेंगे, खटिया तोड़ते रहेंगे, घर वालों से सेवा-चाकरी कराएंगे और उन्हें भी तंग करते रहेंगे। ये लोग बिना मेहनत किए कमाने-खाने के साथ ही अपने आपको भले ही चतुर मानते रहें और यह दंभ भरते रहें कि दुनिया को मूर्ख बनाकर माल बना रहे और मौज मार रहे हैं लेकिन इन लोगों को शायद यह पता नहीं कि जिस प्राप्त समय का वे निरादर कर रहे हैं वह समय ही उनका चुपचाप किश्तों-किश्तों में क्षरण कर रहा है। जो समय का उपयोग नहीं करता है, समय उन्हें खा जाता है। समय की पाबन्दी का संबंध हृदय के भावों से है।

टिकटों में नहीं, सीटों पर मिले महिलाओं को आरक्षण

आरती आर जेरथ, वरिष्ठ पत्रकार

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनावों के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। निस्संदेह, यह अच्छी शुरुआत है, क्योंकि लोकसभा में महिलाओं की मौजूदगी महज नौ से ग्यारह फीसदी रही है। इस कमी को पाटने के लिए महिला आरक्षण बिल संसद में लंबित है, जिसे पारित कराने की कोशिशें1996 से ही चल रही हैं। मगर नतीजा अब तक सिफर है। हालांकि यह बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, पर उस समय भी इसके विरोधी कई सांसदों को मार्शल के जरिए सदन के बाहर भेजना पड़ा था। महिलाओं की मौजूदगी लोकसभा या विधानसभाओं में ही नहीं, तमाम निर्वाचित संस्थाओं में अनिवार्य है। इसके प्रभाव को जानने के लिए स्थानीय निकायों में कई अध्ययन हो चुके हैं, जिसके नतीजे दिलचस्प हैं। मसलन, औरतें पंचायतों में जो परियोजनाएं शुरू कराती हैं, वे अपेक्षाकृत जल्दी पूरी होती हैं। वे सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर खासा ध्यान देती हैं। और तो और, वे पुरुषों के मुकाबले कम भ्रष्ट होती हैं। जाहिर है, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। वे आर्थिक और सामाजिक विकास की बड़ी वाहक हैं। यदि लोकसभा और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता है, तो 'मेक्रो पॉलिसी' (बड़े जनसमुदाय को प्रभावित करने वाली नीतियां) के क्रियान्वयन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। फिर, हमने यह भी देखा है कि चुनावों में अब महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में घरों से निकलकर वोट डालने आए महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच महज 1.8 फीसदी का अंतर था। जाहिर है, जब औरतें इतनी बड़ी संख्या में मताधिकार को लेकर मुखर हो रही हैं, तो राजनीतिक रूप से उनका सशक्त होना निहायत जरूरी है। मगर अपने यहां मुश्किल यह है कि चुनावों में टिकटों का बंटवारा उम्मीदवारों की जीत के गणित पर निर्भर करता है। हर पार्टी उसी उम्मीदवार पर अपना दांव खेलने लगी है, जिसमें जीत की संभावना ज्यादा होती है। और यह संभावना काफी हद तक 'मसल' और 'मनी पावर' पर निर्भर है। यही वजह है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री की इस घोषणा में भी कमजोरी दिखती है। उन्होंने लोकसभा-टिकटों में तो महिला आरक्षण देने की बात कही, लेकिन साथ-साथ हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की। संसदीय चुनावों में चूंकि निर्वाचन-क्षेत्र बड़ा होता है और उसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी रहते हैं, इसलिए यहां उनके लिए यह दांव खेलना आसान था, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाने वाले विधानसभा चुनावों में कड़ा मुकाबला होने की वजह से उन्होंने ऐसे किसी एलान से परहेज किया। फिर भी, इस घोषणा की सराहना की जानी चाहिए, और इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। टिकटों में नहीं, बल्कि सीटों के आधार पर महिलाओं को उचित आरक्षण मिलना चाहिए। यदि 50 फीसदी सीटें महिलाओं के खाते में नहीं डाली जा सकतीं, तो 33 फीसदी आरक्षण का वादा पूरा होना ही चाहिए। साल 2014 तक 'गठबंधन धर्म की मजबूरी' के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, मगर आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी इस मामले में नाकाम साबित हुई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने पहले संबोधन में महिला सशक्तीकरण की खूब बातें की थीं। तब भरोसा जगा था कि जो काम यूपीए सरकार नहीं कर पाई, वह भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार जरूर कर सकेगी। मगर यह सरकार भी महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा की मुहर नहीं लगवा सकी।एक बात और, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने अपने सांगठनिक ढांचे में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया था। दुर्भाग्य से यह वादा भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे महिला-प्रतिनिधित्व के प्रति सियासी दलों की मंशा जाहिर होती है। साफ है, महिलाओं को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। नवीन पटनायक की ताजा घोषणा से शायद दूसरे दलों पर दबाव पड़े। मगर यह किस रूप में महिलाओं का सियासी प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा, इसका जवाब फिलहाल नहीं दिया जा सकता।(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बीएसएनएल में आर्थिक संकट, 1.76 लाख कर्मचारियों की सैलरी अटकी

बिजनेस डेस्क।

घाटे से जूझ रही भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की हालत और खराब हो गई है। कंपनी के इतिहास में पहली बार 1.76 लाख कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन नहीं मिला है। इस वजह से देश भर में कार्यरत बीएसएनएल के कर्मचारियों में रोष व्यापत हो गया है। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से मदद करने की अपील की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो कर्मचारियों को सैलरी दे सके। कर्मचारी संघ ने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार कंपनी को वेतन देने के साथ-साथ फर्म को पुनर्जीवित करने के लिए फंड जारी करे। कंपनी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीएसएनएल का लगभग 55 प्रतिशत राजस्व वेतन के भुगतान में जाता है और जबकि कंपनी का वेतन बिल प्रति वर्ष 8 प्रतिशत बढ़ता है। इसका राजस्व स्थिर है। बीएसएनएल के संघों और यूनियनों ने कहा कि रिलायंस जियो के मूल्य निर्धारण के कारण दूरसंचार उद्योग की फाइनेंसियल हेल्थ को नुकसान हुआ है। सिन्हा ने बीएसएनएल (एयूएबी) के सभी यूनियनों और एसोसिएशनों के एक पत्र में कहा, अन्य ऑपरेटरों द्वारा भी वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा है लेकिन वे भारी मात्रा में निवेश करके स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। बीएसएनएल के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने केरल, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और कॉरपोरेट कार्यालय में कर्मचारियों को फरवरी का वेतन देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जब आय उत्पन्न होगी तो कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है, इसलिए वेतन में देरी हो रही है। सूत्र ने बताया कि मार्च महीने के वेतन में कुछ दिनों की देरी होगी, इस तथ्य के बावजूद कि महीने में नकदी प्रवाह आमतौर पर उद्यम व्यवसाय से बिलिंग के कारण अधिक होता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि बीएसएनएल बोर्ड ने बैंक लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक इसे आगे नहीं बढ़ाया है। बीएसएनएल का घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है। इसने वित्त वर्ष 18 के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया।

रिजर्व बैंक बोर्ड ने 'व्यापक जनहित' में नोटबंदी का समर्थन किया

नई दिल्ली।

सरकार के 500 और 1,000 के नोटों को बंद करने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी ने केंद्रीय बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा था, जिसने 'व्यापक जनहित' में प्रस्ताव का समर्थन किया था। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में हालांकि कुछ निदेशकों ने नोटबंदी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव और समाज के कुछ वर्गों को आने वाली मुश्किलों को लेकर चिंता जताई थी। आर गांधी की ओर से रिजर्व बैंक के बोर्ड को 8 नवंबर, 2016 को दिए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दिन पहले आए वित्त मंत्रालय के पत्र में केंद्रीय बैंक को सलाह दी गई थी कि अधिक नकदी की वजह से 'कालाधन' बढ़ रहा है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आधार पर मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं कि रिजर्व बैंक बोर्ड नोटबंदी की जरूरत को लेकर सरकार की दलील से सहमत नहीं था।

इन्हीं खबरों के बाद आधिकारिक सूत्रों ने यह स्पष्टीकरण दिया है। सूत्रों ने दावा किया कि केंद्रीय बैंक ने इस प्रस्ताव को सरकार को 8 नवंबर, 2016 को ही भेज दिया था। बैठक के ब्योरे का जिक्र करते हुए सूत्रों ने कहा कि कुछ निदेशकों का कहना था कि नोटबंदी हालांकि, एक सराहनीय कदम है लेकिन इससे मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी पर कुछ समय के लिए नकारात्मक असर पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि सदस्य अपनी बात रखते हैं जो ब्योरे में दर्ज होते हैं लेकिन सदस्यों के मत समूचे रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सदस्यों के उनके विचार किसी सदस्य को प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करने के रास्ते में अड़ंगा नहीं बनते हैं।

आरकॉम के 260 करोड़ रुपए को लेकर छिड़ा विवाद

नई दिल्ली।

कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के 260 करोड़ रुपए को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल, आरकॉम के कर्जदाताओं ने कंपनी को मिले 260 करोड़ रुपए के आयकर रिफंड पर अपना दावा ठोका है। कर्जदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के सामने कहा है कि इस रकम पर पहला हक उनका है। बता दें कि न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ संयुक्त कर्ज देने वाली फोरम (जेएलएफ) के अन्य सदस्यों ने कहा कि आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत ट्रस्ट खाते और उसकी देखरेख का अधिकार उनके पास है। इस खाते में कंपनी को मिला रिफंड जमा है। वहीं एसबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने जेएलएफ के समर्थन में कहा कि आरकॉम की संपत्ति की बिक्री से 37,000 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होने के लिए जेएलएफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जियो के आरकॉम का पिछला कर्ज चुकाने से इनकार करने की वजह से मामले का समाधान नहीं हो सका। बीते महीने रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया। दरअसल, आरकॉम ने कोर्ट के आदेश के बाद भी स(वीडिश टेलिकॉम कंपनी एरिव(सन की 500 करोड़ रुपए की बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किया था। बता दें कि टेलिकॉम ऑपरेटर कंपनी एरिक्सन ने 2014 में अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम का टेलिकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी।

कोयला घोटाला में केएसए सपीएल की संपत्तियां हुई कुर्क

नई दिल्ली।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में प्रवर्तन हुआ है। निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश की एक कंपनी की 36 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्की की हैं। ईडी ने कमल स्पॉन्ज एंड स्टील पावर लि. (केएसएसपीएल) निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया की राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के सतना में स्थित संपत्तियों मसलन जमीन, संयंत्र, मशीनरी, कार्यालय और कारखाना भवन को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत सोमवार को यह आदेश जारी किया। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में यह सामने आया कि कंपनी को कोयला

ब्लॉक का आवंटन अपने नेटवर्थ और उत्पादन क्षमता के बारे में गलत तथ्य देने के बाद हासिल हुआ। कंपनी कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें थेसगोरा-बी-रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक आवंटन पर दावे के लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करा सके। इसलिए दल्लिी में कोयला घोटाला मामले को देख रही विशेष अदालत ने इससे पहले केएसएसपीएल, अहलूवालिया और तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई द्वारा इस मामले की आपराधिक जांच में दोषी ठहराया था।

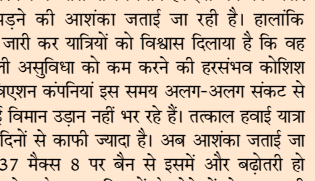

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में सस्ते घर खरीदने का मौका, 12 दिन में शुरू होगा 18 हजार फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। अगर आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बार फिर सस्ते घर की स्कीम लेकर आया है। डीडीए 18,000 नए फ्लैट की बिक्री की स्कीम का ऐलान कर दिया है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के तहत वसंत कुंज और नरेला में फ्लैट की बिक्री की जाएगी। इस स्कीम में एक, दो और तीन कमरे वाले घर हैं। डीडीए के 18,000 फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से शुरू होने वाला है जिसमें 12 दिन का समय बचा है। डीडीए ने हाउसिंग स्कीम 2019 की स्कीम लाने को लेकर सर्कूलर जारी कर दिया है। स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी डीडीए की वेबसाइट पर मौजूद है। डीडीए की इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 25 मार्च 2019 से शुरू होगा। ये फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लिंक हैं। यानी आपको 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट का भी फायदा मिल सकता है। डीडीए की वेबासइट पर जारी सर्कूलर के मुताबिक फ्लैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इनमें 450 एचआईजी और 1,550 एमआईजी फ्लैट हैं। वहीं 8,300 एलआईजी और 7,700 ईडब्लूएस फ्लैट हैं। डीडीए स्कीम में आवेदन करने के लिए शुरूआती रकम भी देनी होगी। आवेदने के साथ ईडब्लूएस कैटेगरी वालों को 25 हजार रुपए देने होंगे। वहीं एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट का आवेदन देने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। एमआईजी और एचआईजी फ्लैट के लिए अर्जी के साथ 2 लाख रुपए देने होंगे। वसंत कुंज में 450 फ्लैट एचआईजी के हैं। वहीं 550 फ्लैट एमआईजी कैटेगरी के हैं। यहां पर 200 फ्लैट एलआईजी कैटेगरी के हैं। वहीं नरेला में 1 हजार फ्लैट एमआईजी कैटेगरी के हैं। वहीं 8200 फ्लैट एलआईजी कैटेगरी के हैं। 7700 फ्लैट यहां पर ईडब्लूएस कैटेगरी के हैं। डीडीए फ्लैट का दाम और ब्रोशर डीडीए की वेबसाइट पर 25 मार्च से पहले अपलोड कर दिए जाएगा। रजिस्ट्रेशन डीडीए की वेबसाइट पर होगा। जो लोग इन फ्लैट के लिए आवेदन करेंगे उनका चुनाव लॉटरी के माध्यम से होगा।

सूचना एवं प्रसारण सचिव ने मीडिया उद्योग में बदलाव की अपील

मुंबई। सूचना एवं प्रसारण सचिव को मीडिया एवं मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) उद्योग में बहुत सारे नियामक हैं। सरकार को इन्हें परस्पर बराबरी के अवसर देने के लिए नीतियां तैयार करने की जरूरत है। अमित खरे ने मंगलवार को कहा कि हमारी नीतियां और नियम सामग्री के आधार पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के आधार पर विकसित किए गए हैं। प्रिंट के लिए अलग नियम है , प्रसारण के लिए अलग नियम और फल्मिों के दूसरे नियम हैं। समाचार पत्रों के लिए भारतीय प्रेस परिषद है लेकिन प्रेस परिषद ऑनलाइन माध्यम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बराबरी के अवसर देने के लिए कुछ नियमों को फिर से संगठित करने और कम से कम कुछ नीतियां तैयार करने की जरूरत है। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमारी सोच प्रसारण क्षेत्र के लिए ट्राई , फल्मिों के लिए सीबीएफसी या प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद जैसे एक और नियामक स्थापित करने की नहीं है। लेकिन एक स्व - विनियमन तंत्र होना चाहिए जहां सभी मंच एक - दूसरे का समर्थन करेंगे।मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों है। ऐसे में नीतियों की नश्चितिता महत्वपूर्ण है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों है। ऐसे में नीतियों की नश्चितिता महत्वपूर्ण है।

अब अंतिम संक्षप्ति जीएसटी रिटर्न फॉर्म में घोषित कर देनदारी की तुलना कर सकेगें जीएसटीएन करदाता

नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पंजीकृत किया है। जिसमें जीएसटीएन ने करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने की सुविधा दी है।। विक्रेता रिटर्न फॉर्म की मदद से कर देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जीएसटीएन ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराता है। जीएसटीएन ने अंतिम बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर -1) में घोषित कर देनदारी को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी है। साथ ही संक्षप्ति बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर -3 बी) में घोषित और भुगतान किए गए कर से जुड़े आंकड़े देखने की भी सुविधा दी है। किसी भी महीने के लिए जीएसटीआर -1 अगले महीने की 11 तारीख तक भरी जा सकती है। कारोबारियों को जीएसटीआर -3 बी रिटर्न और कर भुगतान हर महीने की 20 तारीख तक करना होता है। जीएसटीएन ने बयान में कहा कि जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी अलग - अलग भरे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी सुविधा की जरूरत है जो दोनों फॉर्मों में घोषित कर देनदारी को एक ही जगह पर दिखा सके। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि नई सुविधा करदाताओं को इन दोनों देनदारियों को एक ही जगह पर देखने में सक्षम बनाती है। इससे करदाता जीएसटी पोर्टल पर उनके द्वारा फाइल दोनों फॉर्मों के बीच किसी भी तरह के अंतर को देख सकेंगे। । इससे वह जीएसटीआर -3 बी में घोषित कर देनदारी जीएसटीआर 2 ए में अर्जित दावे का पता कर सकता है। जीएसटीआर -2 ए आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किए रिटर्न पर आधारित होता है।

नीरव मोदी को लेकर मीडिया की रिपोर्ट निराधार: ईडी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालन (ईडी) ने मीडिया की उस रिपोर्ट को निराधार बताया है जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन के सीरियस फ्राड ऑफिस ने गत वर्ष मार्च महीने में ही भारतीय अधिकारियों को भगोड़े नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने की सूचना दी थी। ईडी ने मीडिया की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन के अधिकारियों की ओर से गत वर्ष मार्च में अथवा उसके बाद नीरव के ब्रिटेन में होने को लेकर औपचारिक या अनौपचारिक जानकारी नहीं मिली थी। नीरव मोदी की ब्रिटेन में मौजूदगी की सूचना के बाद ईडी द्वारा उसके प्रत्यार्पण तथा उससे जुड़े मामलों में कोई कदम नहीं उठाने को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए ईडी ने इस संबंध में उसके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी और कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने गत वर्ष मार्च में या उसके बाद नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने को लेकर कोई सूचना नहीं दी थी।

भारत से पंगा लेना पाक को पड़ा भारी, हरी मिर्च ने निकाले धुएं

नई दिल्ली।

पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान की सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। हालत यह है कि पाक में फल एवं सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। पुलवामा हमले से पहले भारत से टमाटर एवं कई हरी सब्जी की पाकिस्तान में सप्लाई हो रही थी जिसे रोक दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान की मंडियों में किसी भी फल-सब्जी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक 12 मार्च, 2019 को लाहौर की मंडी में हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलोग्राम हो गई। वहीं टमाटर के भाव लाहौर के खुदरा बाजार में 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। भारत के अमृतसर से सटे पाकिस्तान के लाहौर में तो मुख्य रूप से भारत के ही टमाटर एवं कई हरी सब्जी की आपूर्ति होती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की समान अवधि में लाहौर में टमाटर की औसत कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम थी लेकिन इस साल सभी सब्जी-फल के दाम 100-200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में हरी मिर्च के दाम शायद ही कभी 100 रुपए किलोग्राम से ऊपर गए होंगे लेकिन पिछले एक महीने से लोकल बाजार में हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। लाहौर के बाजार में हालत यह है कि सब्जी विक्रेताओं ने अपनी रेहड़ी पर हरी मिर्च की बिक्री बंद कर दी है। लाहौर में सब्जी विक्रेताओं को हरी मिर्च नहीं बेचने पर प्रशासन की तरफ से जुर्माना किया जा रहा है। पाकिस्तान में टमाटर का भाव आसमान छू रहा है। लाहौर में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फल-सब्जियां सप्लाई करने वाली आजादपुर मंडी में व्यापारियों ने वहां माल नहीं भेजने का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अटारी-बाघा मार्ग से यहां से रोजाना 75 से 100 ट्रक टमाटर जा रहा था लेकिन इस घटना के बाद ट्रेडर्स ने इसे रोक दिया है। हालांकि अब तनाव कम होने के बाद श्रीनगर से पाकिस्तान के कब्जे वाले चकोटी के बीच ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। रावलपिंडी और लाहौर के बाजारों में भारत से आई सब्जियों से लदे ट्रक पहुंचने लगे हैं। यह सप्लाई आम रूट अब भी बंद होने से ट्रेडर्स को यह महंगा पड़ रहा है।

एसबीआई ने रिलीज करने से इनकार किया आरकॉम का आईटी रिफंड, अनिल अंबानी के जेल जाने का खतरा

मुंबई।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के प्रमुख कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत अन्य वित्तीय संस्थानों की सोमवार को खूब खिंचाई की। न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंकों ने दूरसंचार कंपनी की संपत्ति रिलायंस जियो को बेचकर 37,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने को लेकर गलत एहसास दिलाया। चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने रिलायंस कम्युनिकेशन को कर्ज दे रखे बैंकों खासकर एसबीआई को फटकार लगाई और यह पूछा कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ''आपने जो बातें कही, उसे पूरा करने में विफल रहे। संयुक्त कर्जदाता समूह विफल रहा है। कोई बिक्री नहीं हुई।'' पीठ के अनुसार कर्जदाताओं ने संपत्ति बिक्री के जरिए करीब 37,000 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर एनसीएलएटी को 'सब्जबाग' दिखाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप असफल रहे और अब 260 करोड़ वसूलना चाहते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 260 करोड़ रुपए के आयकर रिटर्न को जारी नहीं करने के लिए स्क्ष्ठ की खिंचाई भी की, जिसका इस्तेमाल ऋष्टश्वद्ब द्वारा स्वीडिश दूरसंचार उपकरण निर्माता एरिक्सन को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। पीठ आरकॉम द्वारा एरिक्सन के पक्ष में कर वापसी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरकॉम को एरिक्सन को इसके 550 करोड़ रुपए के बकाया का एक हिस्सा देने में इसकी मदद करेगा। बता दें कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। अनिल अंबानी को एरिक्सन को 550 करोड़ का बकाया नहीं चुकाकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया। देश की सर्वोच्य अदालत ने तब सुनवाई के दौरान आगे कहा था कि अगर कंपनी चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने में विफल रही तो आरकॉम प्रमुख अनिल अंबानी को तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट ने ऋणदाताओं को यह भी याद दिलाया कि एक बार कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, उधारदाताओं को क्08260 करोड़ नहीं मिलेंगे क्योंकि यह कॉर्पोरेट देनदार के पास जाएगा। एनसीएलएटी ने इससे पहले 15 मई, 2018 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद आरकॉम के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही रोक दी थी। शीर्ष अदालत ने 23 अक्टूबर को आरकॉम को 15 दिसंबर, 2018 तक बकाया राशि देने को कहा था। जानना चाहिए कि आरकॉम पहले ही सुप्रीम के समक्ष 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। इसके अलावा, इसने उधारदाताओं को सीधे एरिक्सन को 260 करोड़ रुपए के आयकर रिफंड जारी करने के लिए कहा है। कंपनी एरिक्सन को ब्याज सहित 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए ।

भारत में बोइंग 737 मैक्स बैन, हवाई किराया हो सकता है महंगा

बिजनेस डेस्क। इथोपियन एयरलाइंस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर भारत ने मंगलवार रात बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया। भारत में इस बैन का सीधा असर स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पर पड़ा है। स्पाइस के पास ऐसे करीब 12, जबकि जेट एयरवेज के पास पांच विमान हैं। इस बैन का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्पाइसजेट ने बयान जारी कर यात्रियों को विश्वास दिलाया है कि वह यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने की हरसंभव कोशिश करेगी। भारत में एविएशन कंपनियां इस समय अलग-अलग संकट से गुजर रही हैं और कई विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं। तत्काल हवाई यात्रा का किराया सामान्य दिनों से काफी ज्यादा है। अब आशंका जताई जा रही है कि बोइंग 737 मैक्स 8 पर बैन से इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जेट एयरवेज के 119 विमानों के बेड़े में से 54 अभी ऑपरेशन से बाहर हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने अबू-धाबी की विमान कंपनी एतिहाद से जेट के निर्बाध संचालन के लिए 750 करोड़ रुपये की मांग की है। एतिहाद की जेट के साथ पार्टनरशिप है। इंडिगो अभी पायलटों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए कंपनी ने अभी से अप्रैल महीने की शुरुआती कुछ दिनों तक रोजाना 30 उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया है। गो एयर भी अपने कुछ प्लेन्स नहीं उड़ा रही है। कुल मिलाकर, हालत यह है कि नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु को भी किराया वृद्धि का डर सताने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने मंगलवार रात को ट्वीट कर बताया कि वह आपातकालीन बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, (एविएशन) सेक्रटरी (पीएस खोसला) को सभी एयरलाइंस के साथ इमर्जेंसी मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा की स्थिति टालने के लिए तात्कालिक योजना तैयार की जा सके।

सीबीआई ने 1000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी में इंफ्रा कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया

नई दिल्ली।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कैनरा बैंक और रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने पर आरोप है कि एक्सप्रेसवे लिमिटेड के कर्जदाताओं समूह को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के श्रीनिवास राव समेत कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है सीबीआई ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सीएमडी के श्रीनिवास राव कंपनी के निदेशकों एन सीतैया, एन पृथ्वी तेजा और कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड , मधुकॉन इंफा , मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड और ऑडिट फर्म त्न कोटा एंड कंपनी त्न का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है। बैंकों के समूह के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर 163 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन बनाने से जुड़ा है। 18 मार्च 2011 को चुना था। यही दिन कंपनी ने रांची एक्सप्रेस - वे लिमिटेड की स्थापना की गई। यह परियोजना डिजाइन , नर्मिाण , वत्तिपोषण , परिचालन और स्थानांतरण मॉडल पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत 1655 करोड़ रुपये थी। इसके लिए कैनरा बैंक की अगुआई वाले 15 बैंकों का समूह 1151.60 करोड़ रुपये का कर्ज देने पर सहमति जताई थी जबकि प्रवर्तकों को 503.60 करोड़ रुपये देने थे। अधिकारियों ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक रांची एक्सप्रेसवे के प्रवर्तक-निदेशकों श्री निवास राव, एन सीतैया और एन पृथ्वी तेजा ने कुल 264.01 करोड़ रुपये की पूंजी गड़बड़ी की है। अधिकारियों ने कहा कि निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों के समूह से 1029.39 रुपये की पूंजी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी। लेकिन परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और ऋण 2018 में गैर-नष्पादित परिसंपत्ति में तब्दील हो गया।

सूरत। उधना जोन शहरी विकास विभाग में अपने सहकर्मी को जन्म दिन का केक खिलाता कर्मचारी।

वराछा में दो लोगों का मोबाइल छीना, मामला दर्ज

सूरत। शहर में दो मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत वराछा पुलिस थाने में दर्ज हुई है। जिसमें एक हीरा श्रमिक और दूसरा सब्जी व्यापारी का मोबाइल झपट लिया गया।

वराछा पुलिस की जानकारी के अनुसार कापोद्रा लक्ष्मणनगर के समीप में कृष्णानगर में रहनेवाले अरविंद समजु वाघेला सब्जी का व्यापार करते हैं। अरविंद दो-ढाई महीने पहले वराछा वेर हाउस के पास एस.एम.सी. संचालित शैचालय के पास रोड पर से गुजर रहे थे। उस समय बाइक पर आए दो अज्ञातों ने उनके हाथ से 10 हजार रुपए का मोबाइल झपट लिया और फरार हो गये। जबकि दूसरी घटना में वराछा भगीरथ सोसायटी में रहनेवाले हरि वल्लभ बालधिया हीरा श्रमिक हैं।

तीन त्योहार विशेष ट्रेनें दौडाने का निर्णय

सूरत। आगामी होली के अवकाश दौरान यात्रियों की बेहतर सुविधा तथा इस सीज़न के दौरान यात्रियों द्वारा की गई विशेष ट्रेनों की मांग के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद एवं पटना तथा गांधीधाम एवं भागलपुर स्टेशनों के बीच दो त्योहार विशेष ट्रेनें विशेष किराये के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रेन सं. 09421/09422 अहमदाबाद-पटना विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (वाया आणंद-गोधरा) और ट्रेन सं. 09421 अहमदाबाद-पटना विशेष ट्रेन अहमदाबाद से सोमवार, 18 मार्च, 2019 को 23.25 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 08.45 बजे पटना पहुँचेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09422 पटना-अहमदाबाद विशेष ट्रेन बुधवार, 20 मार्च, 2019 को पटना से 11.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19.00 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में नडियाद, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा तथा दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन सं. 09451/09452 गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ चलेगी। ट्रेन सं. 09451 गांधीधाम-भागलपुर विशेष ट्रेन शुक्रवार, 15 मार्च, 2019 को गांधीधाम से 17.40 बजे रवाना होगी एवं रविवार, 17 मार्च, 2019 को 18.00 बजे भागलपुर पहुँचेगी।

इसी प्रकार वापसी यात्रा में ट्रेन सं 09452 भागलपुर-गांधीधाम विशेष ट्रेन सोमवार, 18 मार्च, 2019 को भागलपुर से 06.30 बजे रवाना होगी एवं बुधवार, 20 मार्च, 2019 को 08.00 बजे गांधीधाम पहुँचेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यात्रा के दौरान यइ ट्रेन दोनों दिशाओं में भचाऊ, समाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, नडियाड, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमल, मुंगेर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहरेगी।

वेस्टर्न डिस्टर्बन्स की असर की वजह से बदलाव

मौसम में बदलने और ओले की असर से किसान चिंतित

अहमदाबाद। बुधवार को सुबह से ही उत्तर गुजरात और अहमदाबाद सहित राज्य के कई शहरों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई क्षेत्रों में बादल छाया हुआ मौसम देखने को मिला। अब आगामी २४ घंटे में उत्तर गुजरात में बारिश होने की मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। जिसे लेकर अब किसान फिर एक बार चिंतित हो गये है क्योंकि, यदि ओले पड़ेंगे या हल्की बारिश होगी तो गेहूं, वरियाली, जीरा, मकई सहित की फसल को गंभीर नुकसान हो ऐसा है। वेस्टर्न डिस्टर्बन्स की असर की वजह से बुधवार को सुबह से ही अहमदाबाद, उत्तर गुजरात सहित के राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाया हुआ मौसम देखने को मिला। बादल छाया मौसम छा जाने की वजह से शहर सहित राज्य के लोगों को गर्मी से एक प्रकार से राहत मिली लेकिन कहीं तो, एकदम बादल छाया हुआ और ओले की स्थिति बनने से किसान चिंतित हो गये। दूसरी तरफ, मौसम विभाग द्वारा मौसम में बदलाव और मौसम में उल्लेखनीय बदलाव की वजह से गुरुवार को उत्तर गुजरात सहित के राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश या ओले की पूर्वानुमान जताया गया है, जिसे लेकर राज्यभर के किसान चिंतित हो गये है क्योंकि ऐसा हुआ तो गेहूं, वरियाली, जीरा, मकई सहित की फसल को गंभीर नुकसान हो और उनकी मेहनत बेकार हो जाए ऐसा है।

भडीयाद उर्स के लिए खमाशा चार रास्ते से भडीयाद जाने के लिए श्रद्धालु निकले थे।

राजकोट पुलिस की कड़ी कार्रवाई से दहशत

राजकोट में प्रतिबंधित पबजी खेल खेलते हुए १० गिरफ्तार

राजकोट पुलिस कमिशनर द्वारा पबजी खेल पर प्रतिबंध है : गिरफ्तार युवकों को बाद में जमानत पर बरी किया

अहमदाबाद। पबजी गेम से बच्चों पर हो रही असर की वजह से राजकोट शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजकोट पुलिस कमिशनर द्वारा पबजी खेल पर कुछ दिनों पहले प्रतिबंध लगाया गया था। फिर भी शहर में किसी को मालूम नहीं हो तथा पबजी खेल लोग खेल रहे थे। इसके खिलाफ शहर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इस घटना में पबजी खेलते राजकोट के १० युवकों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में गिरफ्तार हुए युवकों को जमानत पर बरी किया गया। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पहले राजकोट शहर पुलिस कमिशनर ने अध्यादेश जारी करके पबजी पर प्रतिबंध लगाया था। फिर भी पुलिस को यह खेल खेलते होने की जानकारी मिलने से शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई थी। खेल को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि, पबजी खेल से बच्चों और युवकों में हिंसक प्रवृत्ति का प्रमाण बढ़ रहा है। यह खेल की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बरबाद हो रही है, जिसकी वजह से उनके अभिभावकों की अक्सर शिकायत रहती है।

अब शहर पुलिस ने बुधवार को सात युवकों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की गई थी। जिसकी वजह से राजकोट शहर में पबजी खेल निजी में खेलते लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सात लोगों को बाद में जमानत पर बरी किया गया। उल्लेखनीय है कि, राजकोट में ९ मार्च से पबजी खेल पर प्रतिबंध लगाता अध्यादेश लागू हो गया है। इसके पहले सूरत में भी पबजी खेल पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिलहाल कच्छ जिले में भी पबजी खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कच्छ जिला कलेक्टर ने अध्यादेश जारी करके खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कच्छ में भी अक्सर शिकायतें सामने आ रही थी कि, यह खेल से बच्चों-युवकों का व्यवहार पर असर हो रहा है। जिसकी वजह से पुलिस ने अपील की है कि, आपके आसपास कोई पबजी खेल खेल रहा हो तो हमें जानकारी दो, आप निकट के पुलिस स्टेशन में भी जानकारी दे सकते हैं।

सौराष्ट्र-उत्तर गुजरात में मौसम बदला, मावठ की आशंका

अहमदाबाद। राज्य के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बन्स के चलत मौसम में बदलाव हुआ है। आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए है। सौराष्ट्र के राजकोट समेत कई इलाके और उत्तरगुजरात के कई जिलों में हल्की सी बारिश हुई।

पिछले कई दिनों से राज्य में मिश्र मौसम में अनुभव हो रहा है। सुबह और रात्रि के समय ठंड और दोपहर के समय गर्मी का लोग अनुभव कर रहे हैं। दोहरे मौसम के चलते सर्दी, जुकाम और स्वाइन लू जैसी बिमारियों में वृद्धि हुई है। आज सुबह से राजकोट में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। कई इलाकों में हल्की सी बारिश हुई। वहीं उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के थराद, धानेरा सहित तहसील और साबरकांठा जिले के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। सुबह से मौसम में बदलाव के चलते किसानों में चिंता फैल गई है।

तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से विवाद

प्राइवेट कंपनी द्वारा कर्मचारियों द्वारा शोषण हो रहे होने का आरोप, कर्मचारियों ने रास्ते पर बैठकर विरोध किया

अहमदाबाद। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते यूडीएस कंपनी के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। जिसकी वजह से नाराज हुए १०० से ज्यादा कर्मचारी अचानक हड़ताल पर चले गये है। प्राइवेट कंपनी द्वारा स्थानीय कर्मचारियों द्वारा शोषण हो रहे होने का गंभीर आरोप लगाये गये। जिसे लेकर अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मामले में काफी विवाद हो गया है।

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण हुआ तब से कोई न कोई विवाद सामने आता रहा है। पहले भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने का विवाद सामने आ चुका है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के टेन्ट में आग सहित की घटनाएं और विजिटर्स के लिए पर्याप्त सुविधा और व्यवस्था नहीं होने सहित के कारणों को लेकर कई विवाद सामने आये

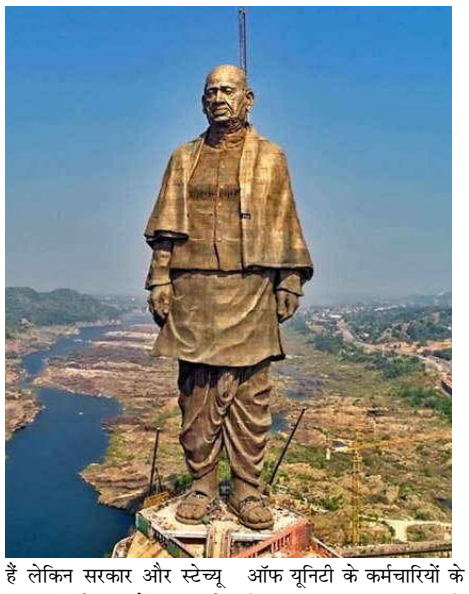

हैं लेकिन सरकार और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी शासकों द्वारा अभी तक विवाद मुक्त माहौल के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के कर्मचारियों के वेतन का नया एक विवाद सामने आया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से वह नाराज हो गये है। बारबार की पेशकश होने के बावजूद भी वेतन नहीं मिलने पर नाराज कर्मचारी बुधवार से अचानक हड़ताल पर चले गये। इतना ही नहीं १०० से ज्यादा कर्मचारी खुलेआम में रास्ते पर बैठकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करके शासकों के विरूद्ध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि, जहां तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल चालू रहेगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सिक्युरिटी, चेकिंग, गार्डनिंग, सफाई, लिफ्ट मेन, टिकट चेकिंग सहित काम करते कर्मचारियों को यूडीसी कंपनी ने अनियमित वेतन दिया जाता है। जिसकी वजह से परिवार का गुजारा चलाने में परेशानी हो रही है। कंपनी द्वारा निर्दोष और काम करते कर्मचारियों का गंभीर शोषण रहा है। कर्मचारियों यह शोषणयुक्त नीति से परेशान है।

चुनाव लड़ने के इच्छुक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढी

अहमदाबाद। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विसनगर कोर्ट की सजा पर स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर. पी.ढोलरियाने हार्दिक की अर्जी को नोट बी फोर मी कहकर नकार दी।

पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान महेसाना जिले के वीसनगर के भाजपा विधायक की ओफिस में तोडफोड के मामले में हार्दिक पटेल विसनगर कोर्ट में दो वर्ष की जेल की सजा हुई है। हार्दिक ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विसनगर कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी की थी। रिप्रेझन्टशन ओफ पीपल्स एक्ट के तहत जेल की सजा भुगत रहे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हार्दिक बिना किसी अवरोध के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी की थी। आज हाईकोर्ट के जस्टिस आर.पी.ढोलरिया ने हार्दिक की अर्जी पर सुनवाई के लिए इन्कार कर दिया।

७०,७१४ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे

अहमदाबाद जिले में ५४.३१ लाख मतदाता मतदान करेंगे

५६२७ मतदान केन्द्र, १०५ सखी मतदान केन्द्र होंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगी

अहमदाबाद। आम लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी महीने में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आचारसंहिता को लागू किया गया है। अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र में २१ विधानसभा सीटें शामिल है। चुनाव मुक्त और निष्पक्ष माहौल में आयोजित हो सके इसके लिए जिला प्रशासन ने काम किया है। आचारसंहिता और जिले में शुरू की गई चुनाव की तैयारियों मामले में आयोजित की गई पत्रकार परिषद में अहमदाबाद जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे ने बताया कि, अहमदाबाद जिले में कुल ५४,३०,९१७ मतदाता है। जिसमें २८,३९,५५६ पुरूष मतदाता तथा २५,९१,२२२ महिला मतदाता और १३९ थर्ड जेन्डर मतदाता शामिल है। हालांकि नए मतदाता रजिस्ट्रेशन का कामकाज २२ मार्च तक चालू रहेगी यह उन्होंने बताया।

जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे ने बताया कि,

अहमदाबाद जिले में १८ से १९ वर्ष की उम्र ग्रुप के ७०,७१७ मतदाता है इस बार पहली बार मतदान करेंगे। जबकि २८९२ सर्विस मतदाता है। अहमदाबाद जिले में १९२३ मतदान केन्द्र स्थलों पर ५६२७ मतदान केन्द्र है। अहमदाबाद जिले में इवीएम और वीवीपेट की संख्या १३० फीसदी है। इसके अलावा १०५ सखी मतदान केन्द्र होंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगी। इसी तरीके से सभी विधानसभा प्रति क्षेत्र एक यानी कि पूरे जिले में २१ मतदान केन्द्र दिव्यांग लोगों द्वारा संचालित होंगे। इसके पीछे दिव्यांग लोगों को आगे लाने का चुनाव आयोग का उद्देश्य है यह पांडे ने बताया। जिले में आचारसंहिता को सख्ती से लागू किया जा रहा है। चुनाव का ऐलान होने से शहर-जिले से पोस्टर्स-बैनर्स-झंडे आदि हटाने का अभियान शुरू किया गया। अभी तक में ५१६४ पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे आदि हटाये गये हैं। जिले में खर्च नियंत्रण सेल कार्यरत कर दिया गया है। इसके लिए देखरेख और नियंत्रण के लिए एफएसटी की ६३, एसएसटी की ६३, वीएसटी की ६३, वीवीटी की ६२, एटी की २१ तथा एइओ की २१ टीमें बनाई गई है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)